कड़ी मेहनत के बाद निखरा है गांव नरियाला

सरपंच योगेन्द्र ने पर्यावरण संरक्षण को यहाँ कर दिखाया

चन्द्रप्रकाश

सरपंच योगेन्द्र कुमार

बल्लभगढ़: पृथला विधानसभा का नरियाला ऐसा गाँव है जिसकी अपनी कोई आमदनी नहीं है, इसके बावजूद यहाँ विकास होता हुआ दिखता है। पंचायत पर्यावरण को लेकर बहुत जागरूक है। नरियाला के सरपंच योगेन्द्र कुमार का कहना है कि गाँव में किसी भी विकास कार्य को कराने के लिए हमें कड़ी मेहनत और भागदौड़ करनी पड़ती है। एमएलए, एमपी और चेयरमैन के सहयोग से हम लोग सभी सरकारी स्कीम गांव में लेकर आए।

सरपंच योगेन्द्र ने बताया कि हमारा गांव फरीदाबाद जिले की सबसे स्वच्छ पंचायत का खिताब जीत चुका है। पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर हमने समय-समय पर पौधारोपण के आयोजन किए। जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हमने कड़े इंतजाम किए हैं। घर-घर तक पानी की पाइप लाइन पंहुचाने के साथ ही हमने पानी की बर्बादी को रोका, हर घर में पानी की टोंटी लगवाई।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र की जर्जर स्थिति को संवारा, बाउंड्री और कच्चे रास्तों पर टाइलें व पेड़-पौधे लगवाकर उसे प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान किया।

गांव में चार कम्युनिटी सेंटर हैं। उनमें बिजली,पानी और शौचालय आदि की व्यवस्था कराई। अब गांव के सभी वर्गों के लोग अपने शादी व अन्य घरेलू कार्यक्रम इन्ही में करते हैं। गांव में पांच भव्य चौपालों का निर्माण कार्य करवाया। जिनमें दो ब्राह्मण, एक बघेल, एक बाल्मीकि और एक जाटव समाज की चौपाल है, जिनकी भव्यता देखते ही बनती है।

वैसे ये समझ से बाहर है कि जातियों पर आधारित चौपालें बनाकर जातिवाद को खत्म किया जा रहा है या उसे मजबूत किया जा रहा है।

सरपंच योगेन्द्र के मुताबिक़ गांव में करीब 95 प्रतिशत घरों में हमने पीएनजी गैस कनेक्शन करवाए। घर-घर तक पीने के स्वच्छ पानी की 3000 मी. पाइपलाइन बिछवाई। हमने गांव में पिछली पंचायत के अधूरे कार्यों को पूरा करवाते हुए सरकारी स्कूल में आठ कमरों का निर्माण कार्य करवाया। बच्चों के दौड़ने लिए ट्रैक बनवाया और खेल के मैदान का सुन्दरीकरण किया। स्कूल के मैदान में 200 मीटर बोर करवाकर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया।

गांव के लोग पशुओं की चिकित्सा को लेकर बहुत परेशान थे, जिसको ध्यान में रख हमने मवेशी अस्पताल के लिए एक एकड़ जमीन आरक्षित की। अब गांव में पशु चिकित्सकों का स्टाफ बैठने लगा है। यह कार्य हमारे कार्यकाल में ही सफल हो पाया है।

सरपंच योगेन्द्र ने बताया कि जगमग स्कीम के तहत अब गाँव का हर चौराहा 24 घंटे जगमग रहता है। नरियाला गांव की सबसे प्रसिद्ध जगह है ग्रामीण क्रीड़ा स्थल। जिसके सौंदर्यीकरण के साथ हमने बागबानी कराई व पार्कों के साथ-साथ टाइलें लगवाकर टहलने का मार्ग बनवाया। इसके साथ ही इसमें एक लाइब्रेरी की स्थापना करवाई। समय-समय पर हमने गांव के विकास के लिए रोटरी क्लब और एनएचपीसी से सहयोग लिया। जिसमें लाइब्रेरी, बच्चों के लिए हैंडवॉश व स्कूल में पानी के कूलर लगवाए।

सरपंच का कहना है कि राजनीति से हमारे परिवार का दूर से भी काई संबंध नहीं था। गांव की मिट्टी से स्नेह, लगाव और सभी वर्गों के आपसी भाईचारे ने ही हमें यह सम्मान दिलाया है। हमने अपनी सरपंची के कार्यकाल को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से गांव के हित में व्यतीत किया है। हमने कभी इस पद के प्रति दुरुपयोग की भावना नहीं रखी।

कठिन प्रश्न / किसान बिल

किसने बिल बनाया ?
सरकार ने
बिल का विरोध कौन कर रहा ?
किसान
बिल का समर्थन कौन कर रहा ?
अम्बानी और अडानी
तो बिल किसके फेवर में हुआ ?
लास्ट वाला प्रश्न कितना कठिन है न ??

- पंकज मिश्र

श्रम एक पुलिस अफ़सर ने गुडईयर यूनियन की रखी थी नींव

सतीश कुमार

सुनने में बड़ा अजीब लगता है एक पुलिस अफ़सर का मज़दूर बनना और फ़िर मज़दूर नेता बनना। लेकिन यह शत प्रतिशत सही है। सन 1961 में बतौर एएसआई थाना बल्लबगढ़ में तैनात करतार सिंह ने थानेदारी छोड़ कर गुडईयर में मज़दूरी इसलिये शुरू नहीं की थी कि उन्हें मज़दूर वर्ग से कोई विशेष लगाव था जिसके चलते वे मज़दूरों के बीच रह कर उनकी परिस्थितियों का अध्ययन करना चाहते थे और उसके बाद उनके हकूक के लिए कोई संगठन खड़ा करना चाहते थे। दरअसल नये-नये थानेदार बने करतार सिंह को वह सब मौज-मस्ती नहीं मिल पाई थी जिसकी लालसा लेकर वे भर्ती हुए थे। उसके बरक्स रात-दिन की नौकरी और ऊपर से अफ़सरों की डांट-फ़टकार, वेतन मात्र 130-35 रुपये मासिक। दूसरी ओर गुडईयर के मज़दूर को आठ घंटे की नौकरी करने पर 200 रुपये मासिक से अधिक मिल रहे थे। बस यहीं करतार सिंह मार खा गये और जा पहुंचे मज़दूरी करने गुडईयर में।

जब मज़दूर की कठिन परिस्थितियां उन्हें भुगतनी पड़ी तब उन्हें थानेदारी याद आने लगी। नौकरी तो खैर कम्पनी की छोड़नी ही थी लेकिन छोड़ने से पहले यूनियन का झंडा गाड़ दिया। पहली मीटिंग गेट पर न करके कम्पनी फ़्लोर (कार्यस्थल) पर ही कर डाली। कम्पनी ने गेट से बाहर किया तो वापस पुलिस में आ गये। यह सब एक साल के भीतर हो गया। आमतौर पर इस तरह दोबारा से महकमे में आना आसान नहीं होता, लेकिन करतार के ससुर चौधरी पीरू सिंह के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों से घनिष्ठ सम्बन्धों के चलते उन्हें पुन: पुलिस में रख लिया गया था। इस बार पुलिस में आते ही उन्होंने अपने असली रंग दिखाने शुरू किये। तमाम, जिन मौज मस्तियों की उन्होंने कल्पना की थी वे सब पूरी कर डाली। चौटालों के राज में तो उन्होंने तमाम सीमायें लांघ डाली। चौटालों के गृह ज़िले सिरसा व मेरे गृह ज़िले भिवानी में बतौर एसपी तैनाती के दौरान उन्होंने अच्छे-खासे खलनायक की भूमिका निभाई थी। जानकार तो यहां तक भी कहने से नहीं चूकते कि औमप्रकाश चौटाला के प्रति अपनी वफ़ादारी निभाने के लिये महम चुनाव में उन्होंने खुल कर गुंडागर्दी कराई थी, यहां तक कि चुनाव लड़ रहे अमीर सिंह की हत्या का दोष भी उनके सिर लगाया जाने लगा।

खैर, जो भी है बतौर एक पुलिस अफ़सर करतार सिंह का ट्रेड यूनियन आन्दोलन से कोई घनिष्ठ लगाव-जुड़ाव नहीं था। यह तो केवल मजबूरी एवं मुगालते का सम्बन्ध था यानी गले पड़ा ढोल करतार सिंह को बजाना पड़ा और यूनियन का गठन हो गया। इस सम्बन्ध में इन सब बातों का उल्लेख करना इसलिये भी जरूरी समझा गया ताकि मज़दूर वर्ग समझ सके कि कैसे-कैसे लोग इस आन्दोलन में न केवल आ जाते हैं बल्कि शीर्ष तक भी पहुंच जाते हैं। ऐसे में मज़दूर वर्ग को अधिक सावधान रहना चाहिये और हर चमकने वाली पीली धातु को सोना नहीं समझ लेना चाहिये।

वापस लौटते हैं गुडईयर में मेरी अपनी कहानी की ओर। कम्पनी द्वारा मज़दूरों पर की जाने वाली किसी भी कार्यवाई से बचाव के लिये वे यूनियन की शरण में जाकर नौकरी से हाथ धोने की बजाय मुझे अपनी ढाल बनाने लगे। इस तरह के अनेको उदाहरण बीत जाने के बाद कम्पनी ने यह सोच कर मुझे निकाल बाहर किया था कि अधिक से अधिक यदि मैं केस जीत कर भी आ जाऊंगा तो कम्पनी बकाया वेतन देकर अपनी जान छुड़ा लेगी जिसके बदले कम्पनी अपना कारखाना तो अपने मुताबिक (शान्ति से) चला लेगी। वैसे उस जमाने में लौट कर यानी केस जीत कर कोई भी कम्पनी में वापस आ नहीं पाता था। मेरे मामले में भी मैं भले ही सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और हर कोर्ट में केस जीतता रहा परन्तु कम्पनी ने प्लांट के भीतर काम पर लेने की बजाय गेट पर ही वेतन व अन्य सुविधायें मुझे देते रहना बेहतर समझा।

22 जून 1978 को बर्खास्त होने के दो-तीन दिन बाद मैंने जम कर गेट मीटिंग ली। मज़दूरों का भरपूर समर्थन व उनके उत्साह को देखते हुए मैंने यूनियन को भंग कर नये चुनाव की घोषणा कर दी। उस वक्त के चलन अनुसार तीन-चार सप्ताह बाद की कोई तारीख चुनाव के लिये तय हो गयी। इसके लिये मज़दूरों की भीड़ पथवारी मंदिर, जहां आजकल बल्लबगढ उपमंडल के कार्यालय कायम हैं, एकत्र हो गयी और ध्वनि मत से मुझे महासचिव व कंवर सिंह को अध्यक्ष चुन दिया गया। अध्यक्ष, मात्र रबड़ स्टैंप था जिसे जातिगत आधार पर संतुलन हेतु बनाया गया था। यह तख्तापलट कोई बहुत आसानी से नहीं हो गया था। चुनाव की निश्चित तिथि तक के समय में दोनों ओर से तगड़ा चुनाव अभियान चला था जिसमें मैनेजमेंट ने भी जम कर अपनी भूमिका निभाई थी। जाहिर है मैनेजमेंट किसी भी कीमत पर, मेरे यूनियन नेतृत्व के रूप में अपने लिये सिर दर्दी पैदा नहीं होने देना चाहती थी। लिहाजा पथवारी मंदिर पर भारी हंगामे व खींच-तान के बाद मेरे नेतृत्व में यूनियन का गठन हो गया।

यूनियन नेतृत्व के इस परिवर्तन का प्रभाव भी तुरंत नज़र आने लगा था। प्रबन्धन ने मज़दूरों को दबाने के लिये फ़िजूल के मीमो (चार्जशीट) आदि जारी करने छोड़ दिये। जिन छोटी-छोटी बातों को लेकर कार्यस्थल पर कहा-सुनी हो जाती उन पर आपसी सहमती से काम होने लगा। मज़दूर अब काफ़ी राहत महसूस करने लगे थे। इसके चलते जिस जोश से मज़दूरों ने यूनियन का तख्ता पलट कर अपनी यूनियन बनाई थी, उनका जोश दिनों-दिन बढने लगा। वे कई बार सीमायें भी लांघने लगे, प्रबन्धन या तो नज़रंदाज़ करता या फ़िर यूनियन के साथ वार्ता करके मामले को रफ़ा-दफ़ा कर देता। परन्तु 18-19 जनवरी 1979 की रात तमाम मज़दूरों व कम्पनी पर भारी पड़ गयी। रात के साढे 12 बजे कारखाने में काम बंद हो गया जो 70 दिन तक बंद रहा। बात बहुत मामूली सी थी या यूं कहें कि बात कुछ भी नहीं थी। हुआ यूं था कि 18 जनवरी को कम्पनी ने तेज सिंह नामक एक श्रमिक को सस्पेंड कर दिया, सस्पेंशन पत्र उसे सुबह उस वक्त दिया गया जब वह रात की पारी खत्म करके सुबह साढे आठ बजे घर (दिल्ली) जा रहा था। उसने इस पत्र के बारे मुझे बताने एवं जवाबी कार्यवाही आदि करने की बजाय वह चुप-चाप कम्पनी की बस में बैठ कर घर चला गया और अगली ड्यूटी करने फ़िर से रात्रि 12 बजे कम्पनी में आ गया। नियमानुसार सस्पेंड वर्कर को सिक्योरिटी वाले गेट पर ही रोक देते हैं परन्तु दिल्ली से आने वाली बसें सीधी भीतर आ जाती हैं लिहाजा वह भीतर आ गया। जब उसे बाहर जाने के लिये कहा गया तो उसने तरह-तरह की बहानेबाज़ी करके जाने से इन्कार कर दिया और हंगामा करके काम बंद करा दिया।

मैं तो कम्पनी से पहले ही बर्खास्त था और यूनियन प्रधान कंवर सिंह रात की ड्यूटी समाप्त करके साढे 12 बजे बस में बैठ कर पलवल की ओर रवाना हो गये। यानी कि कंपनी में हंगामा हो रहा था, प्लांट बंद हो रहा था, स्थिति को सम्भालने की बजाये उन्होंने घर की ओर निकल जाना बेहतर समझा। सुबह करीब चार बजे यूनियन कार्यकारिणी सदस्य गुलाब मेरे कमरे पर पहुंचा जो कम्पनी से करीब दो किलोमीटर दूर गुरगांव नहर किनारे था। सूचना पाकर मैंने उन्हें काफ़ी हड़काया कि जब प्रधान सहित कुछ अन्य कार्यकारिणी सदस्य मौजूद थे तो हड़ताल का फ़ैसला कैसे लेने दिया गया? सुबह करीब आठ बजे मैं गेट पर पहुंचा, बाहर आने वाली शिफ्ट व भीतर जाने वाली शिफ़्ट को काफ़ी समझाया, लेकिन रात भर में सभी के तेवर काफ़ी तीखे हो चुके थे, एक ही मांग थी कि तेज सिंह का सस्पेंशन रद्द किया जाय।

कार्यकारिणी की मीटिंगों के दौर चले, कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि प्लांट चला दिया जाय और तेज सिंह का फ़ैसला बाद में करा लेंगे, सभी चाहते थे कि पहले उसका फ़ैसला हो तब प्लांट चलेगा वरना यूनियन की तो बड़ी बेइजती हो जायेगी। मैंने हर तरह से समझाया कि इस तरह से हड़ताल नहीं की जाती तो मुझे ही कम्पनी से मिला हुआ कहा जाने लगा। मेरा अन्तिम तर्क कि मैं तो पहले से ही बाहर हूं और इस हड़ताल में न जाने कितने और बाहर आ जायेंगे तथा हज़ारों मज़दूरों का वेतन मारा जायेगा, भी किसी काम न आया और उस अवांच्छित हड़ताल का नेतृत्व न चाहते हुए भी मुझे करना पड़ा। दूसरे शब्दों में कहा जाये तो मैं अपनी कार्यकारिणी सहित अपने मज़दूर साथियों को एक सही बात को मनवाने में नाकामयाब रहा मजे की बात तो यह थी कि मैं तो केवल महाचचिव था प्रधान का पद तो कंवर सिंह के पास था, जिसकी कतई कोई जिम्मेदारी नहीं समझी गयी।

(सम्पादक मज़दूर मोर्चा)